वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय आयोजना में 300 करोड़ रुपये की जिस रकम का उल्लेख किया गया है, उसका सम्बन्ध चौथी आयोजना के दौरान, देश में गैर-सरकारी पूंजी निवेश के लिये विदेशों से प्राप्त होने वाले कुल ऋणों तथा निवेश की रकमों से है। अनन्तिम अनुमानों के अनुसार 1969-70 अर्थात चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान 111 करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी देश में आई। बाद की अवधि के बारे में ऐसी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। यह मान लेने के बावजूद कि 1969-70 के आंकड़ों में सरकारी उद्यमों में विदेशी निवेश की रकमें शामिल हैं यह बात सहज रूप से मानी जा सकती है कि सूमची चौथी आयोजना की अवधि में निर्धारित 300 करोड़ रुपये का लक्ष्य पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

जहां तक पिछले कुछ समय की प्रवृत्तियों का सम्बन्ध है, देश में आने वाली कुछ विदेशी पूंजी के निम्नलिखित आंकड़ों से जिनमें सरकारी संस्थानों से प्राप्त ऋण-पूंजी के आंकड़े भी शामिल है, गिरावट की निश्चित प्रवृत्ति का पता चलता है।

वर्ष	रकम (करोड़ रुपयों में)
1967-68	170
1968-69 (अनन्तिम अनुमान)	141
1969-70 (-तदेव-)	111

इसका मुख्य कारण विदेशों के सरकारी संस्थानों से ऋणों के आगमन में कमी का होना है। यदि केवल गैर-सरकारी विदेशी श्रोतों से प्राप्त होने वाली पूंजी को आंका जाय तो किसी प्रकार की स्पष्ट प्रवृत्ति का पता नहीं चलता जैसाकि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :-

वर्ष	रकम (करोड़ रुपयों में)
1967-68	114
1968-69 (अनन्तिम अनुमान)	116
1969-70 (-तदेव-)	81

Freezing of wages of employees working in public undertakings

*437. SHRI SAMAR MUKHERJEE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Bureau of Public Enterprises has sent directions to all public sector undertakings not to effect any increase in wages, salaries and fringe benefits to their employees;

(b) if so, a gist of those directions and reasons therefor ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN) : (a) and (b). Finance Ministry have issued instructions to the administrative Ministries and Public Enterprises in October 1971 that there should be no general revision of wages or increase in fringe benefits in the Public Enterprises and institutions where Government have a majority control without prior consultation with the Central Government (administrative Ministry concerned acting in consultation with Finance Ministrp), in view of the present situation caused by the large influx of refugees from Bangla Desh and the consequential need for economy all round.

Increase in price of residual oil sold to Gujarat State Electricity Board

*438. SHRI K. S. CHAVDA.
SHRI P. M. MEHTA :

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether the price of residual fuel oil sold to Gujarat State Electrity Board for Dhuvaron Power plant has been increased from Rs. 45 to Rs. 138 per tonne;

(b) if so, the reason therefor; and

(c) whether Government have offered to refer the matter to arbitration?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI P.C. SETHI) : (a) and (b) Owing to the absence of a settlement on the price of low sulphur heavy stock, also known as residual fuel